साधु सिंह घुमान

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और अन्य

14 फरवरी, 1990

[के.जगन्नाथ शेट्टी और आर.एम. सहाय, जे.जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940: धारा 34 - "कार्यवाही में एक कदम" - क्या है- इसकी व्याख्या।

प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थियों और अन्य लोगों से एक निश्चित राशि की वसूली के लिए दायर किए गए मुकदमे में, पक्षकारों के मध्य एक समझौते के आधार पर, अपीलार्थी ने उपस्थिति दर्ज की और मूल दस्तावेजों के उत्पादन के लिए प्रार्थना की, क्योंकि फोटोस्टेट प्रतियां स्पष्ट नहीं थीं, ताकि लिखित बयान दाखिल किया जा सके।

इसके बाद अपीलार्थी ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 34 के तहत इस आधार पर मुकदमे पर रोक लगाने के लिए न्यायालय का रुख किया कि मामले को शामिल करने वाले वाद करार में एक मध्यस्थता खंड था। यद्यपि प्रत्यर्थी निगम ने ऐसे खंड के अस्तित्व को स्वीकार किया, इसने इस याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने के अनुरोध का विरोध किया कि अपीलार्थी ने वाद की कार्यवाही में कदम उठाए थे, जिसमें लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्थगन लिया गया था। कार्यवाही पर रोक लगाते हुए विचारण न्यायालय ने कहा कि लिखित बयान दाखिल करने के लिए मामले को स्थगित करने का कोई अनुरोध नहीं था।

प्रत्यर्थी-निगम की अपील पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को हटा दिया। अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है।

अपील को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने, अभिनिर्धारित किया :

1.1 अभिव्यक्ति "कार्यवाही में एक कदम" जो प्रत्यर्थी को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 को लागू करने से वंचित कर देगा, वाद में उसके द्वारा उठाया गया हर कदम नहीं है। यह वाद पर रोक लगाने के अधिकार को छोड़ने के लिए एक कदम होना चाहिए। यह मुकदमे की प्रगति में सहायता के लिए एक कदम होना चाहिए। गुण-दोष के आधार पर विवाद का निपटारा करने के उद्देश्य से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करने की दृष्टि से यह कदम जानबूझकर उठाया गया होगा। [356 सी-डी]

1.2 विचारण न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादियों ने केवल वादी को मूल समझौता और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देश की मांग की ताकि वे लिखित बयान दाखिल कर सकें। यह नहीं कहा गया था कि वे लिखित बयान दाखिल करेंगे। उन्होंने गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए कभी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई अन्य कदम नहीं उठाया। मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा करने का अधिकार पक्षों के समझौते द्वारा प्रदान किया गया है और तकनीकी दलीलों द्वारा इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को उठाए गए कदम में पक्ष की परिस्थितियों और इरादे पर गौर करना चाहिए। न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या पक्षकार ने समझौते के तहत अपने अधिकार को छोड़ दिया है। इन सिद्धांतों के आलोक में और 4 जनवरी, 1985 के आवेदन के सार को देखते

हुए, कोई यह राय नहीं बना सकता है कि प्रतिवादियों ने वाद पर रोक लगाने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है और लिखित बयान दायर करने के लिए मुकदमे में एक कदम उठाया है। (357 बी-डी]

यू.पी.राज्य बनाम जानकी सरन कैलाश चंद्र, [1974] 1 एससीआर 31; भारतीय खाद्य निगम बनाम यादव इंजीनियर, [1983] 1 एससीआर 95 और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाम रेनुसागर पावर कंपनी [1987] 4 एस.सी.सी.137, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1201/1990

(सी. आर. सं. 556/87 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 5.6.87 से।)

मुकुल मुद्गल, अपीलार्थी की ओर से।

एस.एस. जवाली, वाई.पी. राव और राजू रामचंद्रन, प्रत्यर्थीगण की और से।

न्यायालय का निर्णय **के. जगन्नाथ शेट्टी, न्यायाधिपति** द्वारा दिया गया था-

विशेष अनुमति दी गई।

भारतीय खाद्य निगम ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के विरुद्ध पक्षकारों के बीच एक करार के आधार पर 2 लाख रुपये की वसूली के लिए वाद दायर किया। नोटिस की तामील के बाद, अपीलार्थी ने 10 दिसंबर, 1984 को उपस्थिति दर्ज की। 4 जनवरी, 1985 को, अपीलार्थी ने निम्नलिखित कहते हुए एक आवेदन दायर किया कि मूल समझौते और अन्य दस्तावेज की फोटोस्टेट प्रति जो वादी द्वारा अपने साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए हैं, दृश्यमान और स्पष्ट नहीं हैं, और प्रतिवादियों के लिए निरीक्षण करना और लिखित बयान दर्ज कराना बहुत मुश्किल है।

3. कि मूल दस्तावेजात, जो वादी के कब्जे में हैं, का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ताकि प्रत्यर्थी लिखित बयान दाखिल कर सकें।

4. अतः ससम्मान पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वादी को वाद के साथ पेश किये गए मूल करार और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आदेश करने की कृपा करें।"

21 जनवरी, 1985 को अपीलार्थी ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 34 के तहत इस आधार पर मुकदमे पर रोक लगाने के लिए न्यायालय का रुख किया कि मामले को शामिल करने वाले वाद करार में एक मध्यस्थता खंड था। भारतीय खाद्य निगम ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने मुकदमे की कार्यवाही में कदम उठाए थे क्योंकि लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्थगन लिया गया था। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया कि मुकदमे में विवादग्रस्त मामले को शामिल करने वाले मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अन्य बातों के साथ-साथ वाद पर रोक लगा दीः

> "..... इस आवेदन में लिखित बयान दाखिल करने के लिए मामले का स्थगन करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं थी। इस आवेदन में निहित प्रार्थना यह थी कि मूल करार और अन्य दस्तावेजात को पेश करने के लिया वादी को निर्देश दिया जाये ताकि प्रत्यर्थी लिखित बयान दाखिल कर सकें।
>
> ..... वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों की प्रार्थना कि उनके लिखित बयान पेश करने से पहले वादी को मूल करार और अन्य दस्तावेजात न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया जाये इसे कार्यवाही में एक कदम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह मामले के लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्थगन बाबत प्रार्थना नहीं थी।"

लेकिन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रस्तुत अपील में विचारण न्यायालय के आदेश को पलट दिया है। उनका विचार था कि प्रतिवादियों द्वारा अपने आवेदन दिनांक 4.1.1985 द्वारा लिखित बयान दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन के लिए किया गया लिखित अनुरोध कार्यवाही में एक कदम था और मुकदमे पर रोक लगाना विचारण न्यायालय के लिए उचित नहीं था।तदनुसार, उन्होंने अपील को स्वीकार किया और स्थगन आदेश को हटा दिया और विचारण न्यायालय को कानून के अनुसार वाद में कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रतिवादियों ने मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए 4 जनवरी, 1985 को आवेदन दायर किया था और लिखित बयान दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए मुकदमे को स्थगित करने की मांग की थी, जिसे निश्चित रूप से कार्यवाही में उठाए गए कदम के रूप में माना जाएगा।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 पर इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जानकी सरन कैलाश चंद्र, [1974] 1 एससीआर 31, (ii) भारतीय खाद्य निगम बनाम यादव इंजीनियर, [1983] 1 एससीआर 95 और हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाम रेनुसागर पावर कंपनी, [1987] 4 एस.सी.सी. 137 पर विचार किया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अभिव्यक्ति "कार्यवाही में एक कदम" जो प्रत्यर्थी को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 को लागू करने से वंचित कर देगी, मुकदमे में उसके द्वारा उठाया गया हर कदम नहीं है। यह मुकदमे पर रोक लगाने के अधिकार को छोड़ने के लिए एक कदम होना चाहिए। यह मुकदमे की प्रगति में सहायता के लिए एक कदम होना चाहिए। यह कदम गुण-दोष के आधार पर विवाद का न्यायनिर्णयन करने के उद्देश्य से न्यायालय की अधिकारिता के समक्ष प्रस्तुत करने की दृष्टि से

जानबूझकर उठाया गया होगा। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के मामले में इस न्यायालय ने पिछले निर्णयों पर विचार करने के बाद कहा (155-56 पर)

> "……इस प्रकार कार्यवाही में एक कदम जो प्रतिवादी को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 को लागू करने से वंचित कर देगा, मुकदमे की प्रगति में सहायता करने या वाद में विवाद के गुणों के निर्णय के उद्देश्य से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने में एक कदम होना चाहिए। यह कदम ऐसा होना चाहिए जो मध्यस्थता समझौते के तहत अधिकार को त्यागने और इसके बजाय मुकदमे में गुण-दोष के आधार पर विवाद को हल करने का विकल्प चुनने के पक्ष के इरादे को स्पष्ट रूप से प्रकट करे। चुनाव या प्रतिज्ञान स्पष्ट पसंद द्वारा या सहमति द्वारा आवश्यक निहितार्थ द्वारा हो सकता है। किसी व्यक्ति का न्यायालय में अपनी शिकायतों का निवारण करने का व्यापक और सामान्य अधिकार पक्षकारों के विवादों को आपसी पसंद के मंच पर निपटाने के अधिकार के अधीन है। न तो अधिकार अवास्तविक है और न ही अधिकार को किसी भी तरह से तकनीकी रूप से पराजित करने की अनुमति दी जा सकती है। किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा कराने के अधिकार को 'मध्यस्थता' के संदर्भ में अस्पष्ट या गलत कहे जाने वाले तर्कों से पराजित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरी ओर, यदि मध्यस्थता को संदर्भित करने के लिए करार स्थापित किया जाता है, विवाद को निपटाने का अधिकार तकनीकी आधार पर मध्यस्थता को विफल नहीं होने दिया जा सकता है।"

इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन में, उन्होंने केवल वादी को मूल समझौते और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की ताकि वे लिखित बयान दाखिल कर सकें। यह नहीं कहा गया था कि वे लिखित बयान दाखिल करेंगे। उन्होंने गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सौंपते हुए कभी कोई अन्य कदम नहीं उठाया। मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा करने का अधिकार पक्षों के समझौते द्वारा प्रदान किया गया है और इस अधिकार को तकनीकी दलीलों द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को उठाए गए कदम में पक्षकार की परिस्थितियों और मंशा पर गौर करना चाहिए। न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या पक्षकार ने सहमति के तहत अपने अधिकार को छोड़ दिया है इन सिद्धांतों के आलोक में और 4 जनवरी, 1985 के आवेदन के सार को देखते हुए, हम यह राय नहीं बना सकते हैं कि प्रतिवादियों ने मुकदमे पर रोक लगाने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है और लिखित बयान दायर करने के लिए मुकदमे में एक कदम उठाया है।

परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए और विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल करते हुए अपील को स्वीकार किया जाता है।

मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

जीएन.

अनुमति स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।